वह अपनी जान हमेशा हथेली पर लेकर चलता है। युद्ध के पूर्व युद्ध अभ्यास किया जाता है। देश में प्रति वर्ष इन वार एक्सरसाइज में कई जल, थल तथा नभ की सेनाओं के व्यक्ति मारे जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ व्यक्तियों के मरने का समाचार मिला है। उनके परिवारों तथा उन शहीदों की विधवाओं को सुविधाएं नहीं मिलतीं जो वार विडोज को मिलती हैं। मैं सरकार से मांग करूंगी कि वार एक्सरसाइज में मरने वाले व्यक्तियों की विधवाओं तथा बच्चों को भी वही सुविधा मिलें जो युद्ध में मरने वालों के परिवारों को मिलती हैं। वे योद्धा भी देश की खातिर जान गंवाते हैं। फर्क इतना ही है कि एक में दुश्मन के गोला-बारूद से जान जाती है तथा दूसरे में स्वयं देश के गोला-बारूद से तथा अपने ही व्यक्तियों की असावधानी से जान जाती है। अतः परिवार में से तो व्यक्ति खेत हुआ ही है। अतः सरकार इस तरफ ध्यान दे तथा अपने नियमों में संशोधन करे। वार विडोज के समान ही वार एक्सरसाइज में हुई विधवाओं को भी सुविधायें दें।

(vi) SHORTAGE OF CEMENT IN NAGALAND.

SHRI CHINGWANG KONYAK (NAGALAND) : I want to draw the attention of the this House and the Government towards the shortage of Cement in Nagaland. The State has been facing acute shortage of Cement resulting in a crisis, particularly for development works of the State. This situation has been created by the non-release of levy cement quota for Government works by the Associated Cement Company Ltd. Calcutta. The Company has been dilly-dallying and on one pretext or the other a part of the quota is invariably made to lapse every quarter. Even after repeated extensions granted by the Government of India and despite deposit of huge amounts in advance, the Company has been playing truant. Right from May, 1982, *i.e.* second quarter, the Company has defaulted in non-release of more than 9500 Mts. of Cement till July, 1983. As a result several construction works of the Government are help up at various stages. Several lakhs of Rupees are locked up in deposite with the Company. Government had to face public criticism because of the fault of the Associated Cement Compony, Calcutta.

Therefore, I urge that the Government should take immediate steps to release the arrear Cement levy quotas from May, 1982 till date to Nagaland and take appropriate action against the concerned authorities of A.C.C. Ltd., Calcutta.

(vii) NEED TO PROVIDE RELIEF TO HANDLOOM WEAVERS.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति जी, हमारे देश के विभिन्न भागों में हथकरघा उद्योग से सम्बद्ध बुनकरों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है। इस उद्योग से संबंधित मजदूर वर्ग की स्थिति और भी अधिक सोचनीय है। सरकार द्वारा जो गरीब दुकानदारों को कर्ज दिया गया है उसे वापस कर पाना उनके लिए कठिन हो गया है क्योंकि इस उद्योग से वे इतना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं कि अपनी जीविका चलाने के आगे वे कुछ भी कर सकें। ऐसी स्थिति में उनका कर्ज माफ किया जाना आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाया है उसका लाभ अधिकांश बुनकरों को नहीं मिल पा रहा है। अत केन्द्र सरकार को चाहिये कि वह शीघ्र बुनकरों को राहत प्रदान करने के लिये ठोस और कारगर उपाय करे ताकि उनका आर्थिक संकट दूर हो सके।